

दिल्ली में मजदूरों के लिये मकानों का निर्माण

631. श्री कंवर लाल गुप्त : क्या श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों में सरकार तथा मिल मालिकों ने मजदूरों के लिए दिल्ली में कितने-कितने मकान बनाये हैं;

(ख) आगामी तीन वर्षों में मजदूरों के लिए कितने मकान बनाने का प्रस्ताव है;

(ग) गत दो वर्षों में किन-किन मिलों के मालिकों को अपने मजदूरों के लिये मकान बनाने हेतु भूमि या ऋण दिया गया है; और

(घ) क्या सरकार आगामी तीन वर्षों में मजदूरों के लिये अधिकाधिक मकान बनवाने के लिये मिल मालिकों से आग्रह करेगी ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भागवत भा आजाद) : (क) कारखानों में काम करने वाले श्रमिकों के लिये दिल्ली प्रशासन 2036 मकान बना रहा है। इनका आवंटन 1969-70 के वित्तीय वर्ष के अन्त तक किये जाने की आशा है। परन्तु मिल मालिकों द्वारा न तो कोई क्वार्टर बनाये गये हैं और न बनाये जा रहे हैं।

(ख) 2036 क्वार्टर पूर्ण करने के अतिरिक्त, दिल्ली प्रशासन द्वारा 1588 और क्वार्टर बनाने का विचार है।

(ग) कोई नहीं।

(घ) इस समय कोई ऐसा कानून नहीं है जिसके अधीन मिल मालिकों को अपने श्रमिकों के लिये मकान बनाना आवश्यक हो। परन्तु दिल्ली प्रशासन अपनी ओर से इस बात का हर सम्भव प्रयत्न करेगा कि वे ऐसे मकानों के निर्माण का कार्य शुरू कर दें।

गेहूँ, चावल और चीनी का उत्पादन

632. श्री कंवरलाल गुप्त :

श्री शारदा नन्द :

श्री रामसिंह अयरवाल :

श्री ओंकार सिंह :

क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गेहूँ, चावल और चीनी का अगले वर्ष के लिये उत्पादन लक्ष्य क्या है; और

(ख) इस सम्बन्ध में देश की कुल मांग कितनी है और सरकार ने कमी को पूरा करने के लिये क्या उपाय किये हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्ना-साहिब शिन्दे) : (क) अगले वर्ष के लिये गेहूँ और चावल के उत्पादन का कोई अलग लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है। तथापि, वर्ष 1969-70 के लिए कुल मिलाकर सभी खाद्यान्नों के उत्पादन का लक्ष्य 1050 लाख मीट्रिक टन है। चीनी का उत्पादन चीनी कारखाने के क्षेत्रों में गन्ने का उत्पादन और चीनी बनाने के लिए कारखानों को मिलने वाली गन्ने की मात्रा पर निर्भर करेगा।

(ख) खाद्यान्नों की मांग अन्य वस्तुओं की मांग की तरह लचीली होती है। एक प्रकार के खाद्यान्न के स्थान पर कुछ हद तक दूसरे खाद्यान्न का उपयोग भी लिया जा सकता है। अतः देश में किसी समयविशेष पर गेहूँ और चावल की अलग-अलग मांग का अन्दाजा लगाना या सभी खाद्यान्नों की मांग का अन्दाजा लगाना भी कठिन है। यह कमी तो केवल उत्पादन में बढ़ोत्तरी कर दूर की जा सकती है। देश में विभिन्न विकास योजनाओं के द्वारा खाद्यान्नों की पैदावार बढ़ाने के लिये पग उठाये गये हैं। तब तक तो विदेशों से कुछ न्यूनतम मात्रा का आयात करना आवश्यक हो सकता है।